संख्या-04/2021-2350/58-2020-24/2019टीसी

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-01-0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-66/बजट/2020-21, दिनांक 02.11.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-01-0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश धनराशि रू0-630.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-420.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-1050.00 के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रु0-939.12 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0-785.77 लाख (रु0 सात करोड़ पचासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) (जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत रु0-471.46 लाख तथा राज्यांश 40 प्रतिशत रु0-314.31 लाख है) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

अनुदान सं0-83 **(धनराशि लाख रुपये में)**

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	मद का नाम	आय-व्ययक में मदवार प्राविधानित धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40के+रा.)	27-सब्सिडी	2349.83	100.61	2249.22	670.90
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय-	152.63	10.27	142.36	114.87
	योग-	**2502.46**	**110.88**	**2391.58**	**785.77**

(रूपये-सात करोड़ पचासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरुप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। योजना का संचालन निर्दिष्ट कार्ययोजना एवं एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदन सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) सामग्री क्रय में एम0एस0एम0ई0, वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय, किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस- 2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/ दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1 -218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमशः 60: 40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

(11) प्रस्तर-8 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(13) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(15) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध मे जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(16) वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(17) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(19) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(20) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए मिशन निदेशक उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(22) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(23) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक मंे लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन-27-सब्सिडी-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय'' के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-36/दस-2021 , दिनांक 12 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-04/2021-2350(1)/58-2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-4/2017-एम0आई0डी0एच0(ई), दिनांक 15.06.2020 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।